

विचार-प्रवाह... एकता की दिशा में कितनी बड़ी पहल



पेज थ्री

देहरादून, शनिवार, 25 सितंबर 2021



मौसम

अधिकतम 27.0° न्यूनतम 24.0°

40243.39

2

ब्रिटिश सांसद ने दी चेतावनी

7

प्रसिद्ध कृष्णा पर गुस्सा हुए कायरन पोलाई

2021 में जातीय जनगणना संभव नहीं

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुराद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी नहीं की। जातीय जनगणना की मांग नहीं मानी गई। वैसे पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की डिमांड भी खारिज हो चुकी है। तब नीतीश कुमार ने भरे मंच से हाथ जोड़कर गुजारिश की थी। जातीय जनगणना के लिए तो 10 दलों की टीम लेकर दिल्ली पहुंच गए थे।

जातीय जनगणना की मुहिम चलानेवाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मोदी सरकार से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ-साफ बता दिया है कि फिलहाल जातीय जनगणना संभव नहीं है। ये एक नीतिगत फैसला है। इसके बारे में कोई निर्देश नहीं दिया जाए। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है

सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना से केंद्र सरकार का इन्कार

जातीय जनगणना पर लालू यादव ने क्या कहा? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने टवीट कर कहा कि जानवरों की गिनती करनेवाली सरकार पिछड़ों की गिनती करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जनगणना में सांप-बिच्छू, तोता-मैना, हाथी-घोड़ा, कुत्ता-बिल्ली, सूअर-सियार सहित सभी पशु-पक्षी पेड़-पौधे गिने जाएंगे लेकिन पिछड़े-अतिपिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह! BJP/RSS को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों?

कि 2021 में जाति जनगणना नहीं की जा सकती है और सोच समझकर ही इसे हटाने का फैसला किया गया है। जनगणना



में एससी और एसटी जातियों की जनगणना की जाती है और वह इस बार भी होगी, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य जाति की गणना इस जनगणना में नहीं होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि महारष्ट्र सरकार को पिछड़े वर्ग के नागरिक पर जानकारी इकट्ठी करने को कहा गया है। इसके जवाब में ही केन्द्र सरकार ने यह बात

अन्य राजनीतिक दल कर रहे जातिगत जनगणना की मांग

शीर्ष अदालत में केंद्र की दलील ऐसे समय में आई है जब उसे विपक्षी दलों और यहां तक कि जदयू जैसे सहयोगियों से जातिगत जनगणना की मांग का सामना करना पड़ रहा है। 20 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था, भारत सरकार ने नीति के रूप में फैसला किया है कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति-वार आबादी की गणना नहीं की जाएगी।

कही है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि जनगणना में 1951 से एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों को आज तक शामिल नहीं किया गया है। 10 पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली तक पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी से जातिगत जनगणना की खूबियां गिनाई थी। मगर एक ही झटके में केंद्र सरकार ने मैसेज दे दिया

कि जातीय जनगणना नहीं होगी। 23 अगस्त 2021 को बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम नीतीश ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उनके साथ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी थे। इन दोनों की पार्टियां बिहार की सत्ता में साझेदार हैं। इनकी भी डिमांड जातीय जनगणना की है। मगर एक ही झटके में नरेंद्र मोदी ने इनके सपने को चकनाचूर कर दिया।

जातिगत गणना में क्या है परेशानी

सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र ने कहा कि जनसंख्या जनगणना जाति पर विवरण एकत्र करने के लिए आदर्श साधन नहीं है। संचालन संबंधी कठिनाइयां इतनी अधिक हैं कि एक गंभीर खतरा है कि जनगणना के आंकड़ों की बुनियादी अखंडता खत्म हो सकती है और मौलिक आबादी स्वयं विकृत हो सकती है। सरकार ने कहा कि एससी और एसटी सूची के विपरीत, जो विशेष रूप से केंद्रीय विषय हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सूची हैं। कुछ राज्यों में, अनाथ और बेसहारा ओबीसी के रूप में शामिल हैं। कुछ अन्य मामलों में, ईसाई धर्म में परिवर्तित एससी को ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके लिए गणक को ओबीसी और एससी दोनों सूचियों की जांच करने की आवश्यकता होगी, जो उनकी क्षमता से परे है।

संक्षिप्त समाचार

महंत नरेन्द्र गिरि की मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) लखनऊ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तथा निरंजनी अखाड़ा परिषद के सचिव रहे महंत नरेन्द्र गिरि की सोमवार को प्रयागराज में मौत मामले की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई की नई दिल्ली यूनिट की छह सदस्यीय टीम इस केस की जांच करेगी।

ओडिशा सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी के उपर एक और कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में अगले 4-5 दिन भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान व गुजरात के कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

तीसरी लहर की तीव्रता दूसरी वेव की अपेक्षा होगी काफी कम रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या

देश में युद्धस्तर पर कोरोना का चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान: सीएसआइआर

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। देश में युद्धस्तर पर कोरोना का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) के महानिदेशक डाक्टर शेखर सी मांडे ने कहा कि हम देश की एक बड़ी आबादी को पहली और दूसरी खुराक का टीका लगवाने में सफल रहे हैं। वैक्सीन बीमारी को काफी हद तक रोकती है, इससे कोरोना की गंभीरता भी कम होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने पर इसकी तीव्रता कम और दूसरी लहर से काफी कम होगी।

वहीं, दूसरी ओर केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 81.39 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज प्रदान की गई है। इसके साथ ही लगभग 86

पिछले 24 घंटों में 31 हजार से ज्यादा आए गए मामले

देश में कोरोना के मामलों की बात करें तो रोजाना 30 हजार के आस पास नए केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी हुए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना के 31,382 नए कोरोना केस आए हैं। इस दौरान 318 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है।

लाखा वैक्सीन की डोज पाइपलाइन में हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने आगे कहा कि 4 करोड़ 23 लाख 43 हजार 720 (4,23,43,720) वैक्सीन की डोज अभी भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोरोना के टीके उपलब्ध कराकर उनका समर्थन कर रही है। कोरोना टीकाकरण अभियान

के चलते केंद्र देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75 फीसद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मुफ्त में खरीद और आपूर्ति करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन को वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी जल्द ही मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डा भारती प्रवीण पवार ने बताया कि उम्मीद है कि डब्ल्यूएचओ जल्द ही कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी देगा।

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। रोहिणी जिला कोर्ट में गैंगवार की घटना ने होश उड़ा दिए हैं। इसने अदालत परिसरों में सिक्योरिटी की भी पोल खोल दी है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने इस घटना को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। उसने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। काउंसिल ने इसके पीछे पुलिस अधिकारियों की लापरवाही को कारण बताया है।

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। दो गुटों की गैंगवार में दिल्ली के कुख्यात अपराधियों में शामिल जितेंद्र मान उर्फ गोगी की टिल्लू गैंग के बदमाशों ने हत्या कर दी। ये बदमाश कोर्ट में वकील के वेश में पहुंचे थे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर जांच कर रहे हैं। कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

इस घटना के बाद अदाततों के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठने लगे हैं। रोहिणी कोर्ट में हुई फायरिंग

फायरिंग

बार एसोसिएशन ने रोहिणी कोर्ट में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया

पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष राकेश सहरावत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इस घटना की निंदा करता है। कोर्ट में इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। दिल्ली CP से बार-बार इसके बारे में कहा जा चुका है। यह और बात है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

सहरावत ने शनिवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा, मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सदस्यों के साथ कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलूंगा। हम उनसे कहेंगे कि दिल्ली पुलिस कोई ठोस कदम उठाए, जिसके कारण ऐसी घटना भविष्य में फिर न हो। जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development

All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding

1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation

A-Z Work to make a Website Engine Friendly. You tell us, we do it.

Gadoli Media Ventures

Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

यूपीएससी एग्जाम 2020 का रिजल्ट घोषित

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा, 2020 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। अपॉइंटमेंट के लिए कुल 761 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। एग्जाम में शुभम कुमार ने पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक (सिविल इंजीनियरिंग) में स्नातक किया है। जागृति

शुभम कुमार को मिला पहला स्थान

अवस्थी ओवरऑल सेकेंड रैंक हासिल करने वाली महिला उम्मीदवारों में टॉपर हैं। उन्होंने MANIT भोपाल से बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में ग्रेजुएशन किया है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बताया कि शीर्ष 25 उम्मीदवारों में 13 पुरुष और

12 महिलाएं शामिल हैं। जिन उम्मीदवारों को रिकमेंड किया गया है, उनमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले 25 लोग भी शामिल हैं। इनमें 7 अर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग, 4 नेत्रहीन, 10 बधिर और 4 मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं।

2016 की टॉपर टीना टाबी की बहन रिया डाबी को सिविल सर्विस परीक्षा में 15वां रैंक हासिल किया है